MR. CHAIRMAN: Now, Shri Parida. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः बजट कम या ज्यादा होने का यह मसला ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Prem Chandji, your question is over. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः उसमें research and development के ऊपर फोकस क्यों नहीं जा रहा है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Your question is over. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Shri Parida.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, there are a number of Agricultural Universities in the country and they are engaged in research work. As my friends have already mentioned, the level of research is not very high which could be utilised for the purpose of developing agriculture. But the seats in agricultural universities are limited. Our country is vast. Is there any plan to introduce Agriculture in the Science stream in colleges where it could be studied as a subject, or taken up as an Honours subject, so that a large number of students could then be educated and trained in the colleges and not necessarily in agricultural universities? Are you thinking on those lines?

डा. संजीव कुमार बालियानः महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, अगर वे व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह मैटर प्रदेश सरकारों से और दूसरी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई मिनिस्टर्स से बात की थी, एक बार एचआरडी मिनिस्टर से भी इस बारे में लगातार बात की थी। शरद पवार जी इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यह इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें मेरे द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। जहां तक सीट बढ़ाने की बात है, उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने इस वर्ष देश भर में जितने भी वेटरनरी कॉलेजेज़ हैं, उनमें जो 60 स्टूडेंट्स प्रति कॉलेज की लिमिट थी, उसको बढ़ा कर पहले ही इस वर्ष से 100 स्टूडेंट्स प्रति कॉलेज कर दिया गया है।

Auction of mobile phone airwaves

*18. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government has successfully auctioned mobile phone airwaves spectrum during March, 2015;

(b) if so, the details thereof and the amount Government will receive from the mobile companies in future; and

(c) the criteria and guidelines fixed by Government for mobile operators?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Government has successfully auctioned spectrum in 2100/1800/900/800 MHz bands during March 2015.

(b) The details of the Auction of spectrum conducted in March, 2015 are as given below:—

Band	On Offer			Realization			
	No. of Service Areas	Quantum of Spectrum (MHz)	Value of spectrum on offer at Reserve Price (₹ cr)	No of Service Areas where Spectrum allocated	Quantum of Allocated Spectrum (MHz)	Value of allocated spectrum at Reserve Price MHz (₹ cr)	Value realized at Winning Price (₹ cr)
2100 MHz	17	85	17555.00	14	70.00	9620.00	10115.41
1800 MHz	15	99.2	8936.20	14	93.80	8292.40	9636.17
900 MHz	17	177.8	40223.80	17	168.00	37841.00	72964.54
800 MHz	20	108.75	13562.50	18	86.25	9710.00	17158.79
	69	470.75	80277.5	63	418.05	65463.40	109874.91

An amount of ₹ 32377.85 crores has been received as upfront payment from successful bidders. An installment of ₹ 15133.36 crores per year would be received from successful bidders, from 2018 onwards for ten years.

(c) Successful Bidders had to make either full upfont payment or Deferred payment, subject to the following conditions:

(i) An upfront payment of 33% in the case of 1800 MHz band, and 25% in case of 900 MHz and 800 MHz bands of the final bid amount to be made within 10 days of declaration of successful bidders and final price;

(ii) There is a moratorium of 2 years for payment of balance amount of one time charges for the spectrum, which shall be recovered in 10 equal annual installments with interest applicable at SBI Base rate.

(iii) The 1st installment of the balance due shall become due on the third anniversary of the scheduled date of the first payment. Subsequent installment shall become due on the same date of each following year.

(iv) The successful bidder shall securitize the annual installment for the deferred payment through a financial bank guarantee (FBG) of an amount of one annual installment.

(v) In case of overdue payments, penal interest shall be charged on the delayed amount from the due date at the prime lending rate of the State Bank of India, applicable on the due date, plus 2% (compounded monthly), and a part of the month shall be reckoned as a full month for the purpose of calculation of interest.

(vi) If due payments are not received within time plus a grace period of 10 days, the sum shall be recovered by encashing the Financial Bank Guarantee.

(vii) In the event of default in payment of installments, in addition to the action as provided in the paras above, DOT may terminate the license and spectrum allotment/assignment, in which case, the allotted/assigned spectrum will revert back to DOT. The FBGs in such cases will be encashed. This would be without prejudice to any other remedy DOT may decide to resort to.

Failing deposit of upfront payment and requisite Bank Guarantees by the successful bidders, the Earnest Money Deposit shall stand forfeited. In case of the date of payment being Saturday, Sunday or a public holiday, the effective date of payment was to be considered as next working day. All payments were to be made by the Successful Bidders through Real Time Gross Settlement (RTGS) into the designated account specified by DoT.

श्री संजय राउतः सर, स्पेक्ट्रम को ऊंची कीमतों पर बिना घोटाले के बेचना मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है और इस नीलामी से सरकार को करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए मिले। उससे जीरो लॉस वाली जो थ्योरी थी पहले की सरकार की, वह गलत साबित हुई। सर, मेरा सवाल यह है कि जो अभी ऑक्शन हुआ है, उस ऑक्शन का असली मकसद क्या था? स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मकसद कंज्यूमर्स को कम रेट पर अच्छी सर्विस, अच्छी सेवाएं देना होता है, लेकिन यहां ऑक्शन का जो उद्देश्य दिखता है, वह है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए। उस मकसद से ऑक्शन किया गया और प्रधान मंत्री जी का 'डिजिटल इंडिया' का जो सपना है, वह हमारे देश का सपना है। हमारे देश में लगभग 90 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और 30 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस ऑक्शन से आपको जो रेवेन्यू मिला है, उससे सरकार को तो पैसा मिला है, लेकिन जो लाखों-करोड़ों कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या सेवा मिलेगी, ज्यादा सुविधाएं क्या मिलेंगी?

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सभापति जी, नई सरकार बड़े पारदर्शी तरीके से इसको पिछले मार्च महीने से शुरू करके देश के सामने लेकर आई है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि लगभग

एक लाख दस हजार करोड़ का मुनाफा सरकार को हुआ है। मैं इसको थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ। Upfront हमको लगभग 32 हजार करोड़ रुपए मिला और आने वाले दस सालों में सालाना 15 हजार करोड़ से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, अगर आने वाले बारह सालों में 2018 से आने वाले टोटल रेवेन्यू को जोड़ दें, तो यह कुल 1 लाख 83 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से यह एक बड़ी उपलब्धि हुई है। हमें विरासत में जो मिला था, उसस देश के अंदर एक confidence पैदा हुआ कि स्पेक्ट्रम में भी यह हो सकता है और उसको यह सरकार ने करके दिखाया। लेकिन माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि उससे आखिर ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और मान्यवर सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। इससे स्पेक्ट्रम का दायरा बढ़ा है, नई स्पेक्ट्रम आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री से लंबे समय से हमारी बातचीत चल रही थी कि हमको कुछ additional spectrum मिले। पिछले सात सालों के विवाद को सुलझाते हुए डिफेंस से additional spectrum आया। Spectrum की band width बढ़ी, उसके कारण सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी। जो कॉल ड्रॉप आउट होती था, अभी भी जो कॉल ड्रॉप आउट ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः सर ...**(व्यवधान)**...

श्री धर्मेंद्र प्रधानः प्रेम चन्द जी, मुझे अपना उत्तर दे देने दीजिए, फिर आपकी supplementary भी ले लूंगा। अभी जो कॉल ड्रॉप आउट होता है, उस कॉल की क्वालिटी बढ़ेगी, ग्रामीण इलाके में विशेष करके उसकी सर्विस बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि पहले टेलीफोन सर्विस voicing होती थी, धीरे-धीरे data आई, data के कई प्रकार के नए-नए आयाम आए। आने वाले दिनों में सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, वह है, भारत के आम जन को 'डिजिटल इंडिया' के साथ जोड़ना। महोदय, यह उसका व्यू है, यह उसकी foundation है, उसमें ग्राहक सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे।

श्री संजय राउतः सर, जो ऑक्शन हुआ, उसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई, ऊँची कीमत पर बोली लगाई। यह कोई चैरिटी वर्क नहीं था, यह कोई चैरिटी का काम नहीं था। जिसने भी यह बोली लगाई, वह कंपनी अपना मुनाफा कमाएगी और उसका बोझ कंज्यूमर पर भी पड़ेगा। हमने यह सुना और पढ़ा है कि ये सारी कंपनियां कॉल रेट्स बढ़ाने की फिराक में हैं। उनकी योजना 15 परसेंट कॉल रेट्स बढ़ाने की है। इस बारे में सरकार क्या करेगी, उन पर कैसे कंट्रोल करेगी? दूसरी बात, आपने 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के रेवेन्यू की जो बात कही है, वह आपको वर्ष 2018 से मिलेगा, लेकिन अभी आपको क्या मिला है, यह भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ।

श्री धर्मेंद्र प्रधानः सभापति जी, अभी तो upfront में सीधा-सीधा 32 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। यह पूरा ट्रांसपैरेंट है और यह वेबसाइट पर है। दूसरी बात, इन्होंने यह शंका व्यक्त की है कि कॉल रेट्स 15 परसेंट बढ़ जाएँगे। महोदय, एक तो कई सालों से हमने यह तय किया हुआ है कि देश के टेलिकॉम सेक्टर में "ट्राई" ही टैरिफ तय करेगी। दूसरा, टेलिकॉम सेक्टर के प्राइस मेकैनिज्म का जो इतिहास है, उससे यह शंका वाजिब है, इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ। जिन्होंने निवेश किया है, क्या वे अपने निवेश का मुनाफा कमाना नहीं चाहेंगे, वे इसे कंज्यूमर्स

के ऊपर पास ऑन करना चाहेंगे, यह एक स्वाभाविक शंका है। सभापति जी, हम यह न भूलें कि इस देश में जब टेलिफोन कंपनियों ने अपना काम शुरू किया, तब वह 17-18 रुपये के एक कॉल पर शुरू हुआ था। आज जब हम टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम के बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं, इसके गेटवे को बड़ा कर रहे हैं, इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और सरकार ने जान-बूझकर इसको टेक्नोलॉजी न्यूट्रल किया है और अब इसमें किसी सीडीएमए या जीएसएम को प्राइऑरिटी देने अथवा इसको ज्यादा उसको कम देने जैसी बात की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। यह टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रहेगी और धीरे-धीरे यह भी संभव है कि यह शंका शायद गलत साबित हो। यह बात भी सुनने में आई है कि 4जी में फ्री टॉकिंग टाइम होगा, यानी बात तो मुफ्त में होगी ही, उसके साथ-साथ सर्विस में भी पैसे आएँगे। इसलिए यह शंका अभी premature है। आने वाले दिनों में सभी ग्राहकों को और सहूलियतें मिलेंगी और उसके साथ-साथ और सेवाएँ भी मिल सकती हैं।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि एयर वेव्स के ऑक्शन के समय क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया या यह कंडीशन इम्पोज़ की गई कि ग्राहकों के हित की रक्षा की जाएगी? आपकी kitty में करोड़ों रुपये तो आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ कॉल ड्रॉप की समस्या भी सामने आ रही है, यानी एक कॉल में तीन-तीन, चार-चार कॉल्स हो रहे हैं। अगर उन कंपनियों के 20-22 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, तो इस वजह से प्रति मिनट उनकी kitty में कितना पैसा जा रहा होगा? इसके साथ ही, ऐड-ऑन सर्विसेज़ के नाम पर वे कभी 30 रुपये तो कभी 50 रुपये का बिल भेज देते हैं। ये जो दंड उपभोक्ता के ऊपर लग रहा है, इससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है, ताकि कंपनियां इस प्रकार का जो शोषण कर रही हैं, वे ऐसा न करें?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सभापति जी, "ट्राई" की यह प्रमुख जवाबदेही है कि मोनोपली न हो और "ट्राई" की जो भूमिका है, वह जो निर्णय करेगी, उससे सरकार भी बँधी हुई है और कंपनियां भी बँधी हुई हैं। बाकी उन्होंने सही कहा है। इसलिए इस बार, मैं स्पेक्ट्रम के बारे में एक ही उदाहरण देता हूँ, क्योंकि इसके साथ कई सारे टेक्नोलॉजी इश्यूज़ जुड़े हुए हैं। पहले 2100, 1800, 900 और 800 मेगाहट्र्ज की अलग-अलग नीलामी होती थी। इसी को एक बड़े बैंडविड्थ के साथ simultaneously नीलामी की गई है, ताकि इसकी टेक्नोलॉजिकल सहूलियत रहे। इन्वेस्टर्स अपने सारे कारोबार करते हुए technology savvy भी हो पाएँ और कोशिश है कि उसमें ग्राहकों को दिक्कत न आए।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, we have learnt that 48,72,027 units of calls have emanated from one telephone number, No. 24371515 in the month of March 2007 alone, which is indicative of the massive multimedia transfer in the underlying connections. It is just one of the 323 lines accounted for over 48 lakh call units in March 2007 alone.

MR. CHAIRMAN: You please put your question.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Almost 49 call units in one month have gone from 323 phone connections.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, it has unlawfully robbed the BSNL during January 2007 to April 2007 and now the BSNL is under a very massive crisis that this year alone, ₹ 7287 crores are lost for BSNL in 2012-13 and in 2011...

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, the supplementary question is not connected with this question.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: It is related to this question.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Mobile phone Airways spectrum...

MR. CHAIRMAN: I will not allow speeches during Question Hour.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: In the Spectrum alone,...

MR. CHAIRMAN: You just put your question.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, every year, BSNL is incurring a loss of ₹ 10,000 crores. Is this true or not? I want to know that.

MR. CHAIRMAN: You can just answer the question.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: This is altogether a separate question. I honour the question. With your permission, Sir, I will inform the hon. Member separately.

श्री अजय संचेती : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो स्पेक्ट्रम के माध्यम से जो पैसा कलेक्ट हुआ है, उसमें मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा कि आजकल सारे शहरों में कॉल ड्रॉप्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब कॉल ड्रॉप होते हैं तो एक ही बार बात करने के लिए तीन-तीन, चार-चार बार एक ही जगह टेलीफोन लगाने पड़ते हैं। तो इसका जो पेमेंट है वह कंज्यूमर को करना पड़ता है। तो जिस तरीके से कम्पनियां स्पेक्ट्रम के लिए पैसा दे रही हैं, क्या वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएगी, ताकि अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर बोझा न पड़े?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, कई सदस्यों ने इस विषय के बारे में चिंता की है। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रम की मल्टी डॉयमेंशनेलटी बढ़ाने का यही उद्देश्य है कि इसमें ग्राहकों को इस प्रकार की दिक्कत आगे न आए। यह प्रश्न वाजिब है, विभाग इसकी चिंता करेगा।

Area under Micro-Irrigation

*19. SHRI C. M. RAMESH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of area under micro-irrigation, including drip and sprinkle irrigation, across the country; and